

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 10 नवंबर 2024, समय 1305 (05 मिनट))

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में डाई अमोनियम फॉस्फेट- डी.ए.पी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसानों को रबी फसलों की बुवाई में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी किसानों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। श्री नायब सिंह ने कहा कि इस समय विभिन्न जिलों में 23 हजार, 118 टन डी.ए.पी का स्टॉक उपलब्ध है। अगले दो से तीन दिनों के भीतर राज्य के विभिन्न जिलों में 9 हजार, 172 टन डी.ए.पी और आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खाद की उपलब्धता के लिए सभी प्रबंध कर लिए हैं। कांग्रेस नेता किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा में खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और इसका वितरण भी सही तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गौ-सेवा आयोग के लिए 400 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है, जिसे आगामी वर्ष में बढ़ाकर 510 करोड़ रुपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेसहारा गौवंश की देखभाल की दिशा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 3 माह में सड़कों पर बेसहारा गौ-वंश दिखाई नहीं देगा। मुख्यमंत्री कल गोपाष्टमी के अवसर पर पंचकूला के गौ वन सेवा धाम में आयोजित उत्सव को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गौवन सेवा धाम की परिक्रमा की और गौ सेवा भी की तथा तुलादान भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गौ-वन धाम गौशाला

को अपने ऐच्छिक कोषसे 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने एक हज़ार गायों वाली गौशालाओं को एक ई-रिक्शा और इससे ज्यादा गायों वाली गौशालाओं को दो ई-रिक्शा खरीदने हेतु प्रति ई-रिक्शा 1 लाख 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब नई गौशाला बनाने के लिए सी एल यू लेने की भी आवश्यकता भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब गौशाला के लिए दान में मिली या खरीदने वाली जमीन की रजिस्ट्री पूर्ण रूप से कर मुक्त की गई है। इसके अलावा ई.डी.सी शुल्क भी नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन हज़ार गायों वाली गौशाला में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए सप्ताह में एक दिन चिकित्सक की सेवाएँ दे जायेंगी। उन्होंने कहा कि देसी गाय पलने वाले किसान को 30 हज़ार रुपए की राशि प्रति वर्ष प्रति गाय का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशाला में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशाला में ट्यूबवेल लगाने के लिए बिजली और सिंचाई विभाग से कोई अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। बेसहारा बछड़ा, बछड़ी, गाय व नंदी को पकड़ कर गौशाला में के लिए प्रति बछड़ा/बछड़ी 300 रुपए, प्रति गाय 600 रुपये और प्रति नंदी 800 रुपए की दर से नकद राशि का भुगतान गौशाला को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में चारे की व्यवस्था का भी प्रबंध करने का सरकार ने निर्णय लिया है। बछड़ों के लिए 20 रुपए, गाय के लिए 30 रुपए और नंदी के लिए 40 रुपए की राशि चारे के लिए प्रदान की जाएगी।

हरियाणा में कल गोपाष्टमी का त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा गायों की पूजा अर्चना कर उन्हें चारा खिलाया गया। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने गोपाष्टमी पर अम्बाला छावनी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि गौ माता को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए, गऊ माता का पालन-पोषण करने से राष्ट्र का गौरव भी बढ़ेगा। कार्यक्रम के उपरांत श्री विज ने रामबाग गौशाला में गऊ माता की पूजा-अर्चना और सेवा की। जींद जिले में जिला मुख्यालय गौशाला में

आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर यज्ञ का आयोजन किया गया तथा गायों की पूजा अर्चना की गई। विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गाय की पूजा कर उसे गौ माता का दर्जा दिया था। करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने गायों की पूजा और सेवा की। इस मौके पर उन्होंने गौशाला में गौ चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन भी किया, जहां घायल एवं बीमार गौवंश का मुफ्त में इलाज किया जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना लागू करने में देरी होने के कारण 2 संयुक्त आयुक्तों, 2 उप नगर आयुक्तों और एक कार्यकारी अधिकारी का 15 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, उभोने गुरुग्राम नगर निगम के क्लर्क संदीप को 50 हजार रुपये की रिश्वत माँगने के एक मामले में निलंबित कर दिया है। गुरुग्राम में शहरी स्वामित्व योजना के एक मामले में लाभार्थी द्वारा पूरी राशि जमा करवाने के बावजूद दो साल से चक्कर लगवाए जा रहे थे और क्लर्क संदीप द्वारा रिश्वत माँगी जा रही थी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव द्वारा अधिकारियों को अगले 3 दिनों में शहरी स्वामित्व योजना के तहत लंबित मामलों में कन्वेयन्स डीड का निष्पादन सुनिश्चित कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, 100 ऐसे मामले, जिनमें पूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है, उनकी कन्वेयन्स डीड का निष्पादन भी 14 नवंबर तक पूरा करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, 2 हजार, 152 लंबित मामलों पर भी आगामी 10 दिनों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
